श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली कानपुर लाइन पर यह सेल्फ डायल योजना कब तक चालू हो जायेगी ? इस का ट्राइल भी हो चुका है।

Shri Bhagavati: Delhi-Kanpur: it is likely to be completed during 1963-64.

Shrimati Savitri Nigam: When this scheme has proved to be so good and so effective, may I know whether an overall plan to connect all the important cities each other has been made and if the answer is in the affirmative, when it will be implemented?

Shri Bhagavati: This equipment is to be introduced in some major stations. There are proposals. It will take some time. Before introducing this system, we have to lay co-axial cables. I have already said that the introduction of this equipment or system depends upon a large number of stable trunk circuits which, again, depend on the laying of co-axial cables.

Shri K. N. Pande: May I know what experience has been gained by the Government by this scheme: whether it is advantageous or disadvantageous?

Shri Bhagavati: They are certainly advantageous. It is a landmark in the history of telecommunication in this country.

Shri Dasappa: May I know when the co-axial cable project is expected to be completed according to the present plan?

Shri Bhagavati: During the Third Five Year Plan period. It is expected that we may complete in the main routes.

श्री भानुप्रकाश सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दिल्ली–आगरा और कानपुर–लखनऊ के पश्चात् वह कौन से भाग्यशाली दो नगर होंगे जिनको कि इस योजना का निकट भविष्य में लाभ होगा ?

Shri Bhagavati: I can hardly say anything.

श्री म० ला० द्विवेदी : जो योजना सरकार ने बनाई थी उसमें किन किन शहरों के बीच में यह योजना चालू करने के लिये प्राथमिकता दी गई है ?

Shri Bhagavati Already these schemes have been sanctioned: Delhi-Kanpur, Delhi-Lucknow, Agra-Kanpur, Agra-Lucknow, Kanpur-Varanasi.

दिल्ली में आयुर्वेदिक कालिज

\+

*७२७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १६ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संपेया १४९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि आयुर्वेदिक कालिज दिल्ली को भारत सरकार के सीधे नियंत्रण मे लाने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : इस कालेज का और अधिक विकास करने के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया बोर्ड ने पांच सदस्यों की एक समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष सुपरिन्टेंडेंड मेडिकल सर्विसेज दिल्ली हैं। इस विषय पर आगे विचार करने से पूर्व, हम इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : यह जो एक छोटी कमेटी बनाकर सुझाव मांगे गये हैं क्या इस का अर्थ यह तो नहीं है कि जो बुनियादी प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार इसको अपने हाथ में ले ले, उसको समाप्त कर दिया गया है या उस पर अभी भी विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस को लेने

की बात का आधार उस कमेटी की सिफारिशों के ऊपर ही होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि इस संस्था को स्थापित हुए यद्यपि इतने वर्ष हो गय और कई बड़े और महान व्यक्तियों का नाम इससे लगा हुआ है फिर भी कई वित्तीय कठिनाइयां, गड़बड़-घोटाले, कुव्यवस्था और कुप्रबन्ध आदि की इस तरह की शिकायतें इसके संबंध में शासन के ध्यान मे आई हैं और क्या उन पर कुछ कार्यवाही की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, मैंने चन्द रोज पहले इसी हाउस में निवेदन किया था कि कैसे हकीम अजमलखां साहब के सुपुत्र ने सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया और उस मुकदमे का फैसला अभी थोड़ ही दिन पहले सरकार के हक में हुआ है । इस दरमियान पहले की निस्बत इस कालिज में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है । कुछ शिकायतें बाकी हैं उन को दुरुस्त करने का इंतजाम किया जा रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद क्या इस कालिज के विद्यार्थियों ने माननीय मंत्री के सामने एक स्मृतिपत्र पेश किया है जिसमें उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि ५ वर्ष की पढ़ाई के बाद वह यह महसूस करते हैं कि उनके डिप्लोमा का कोई मूल्य नहीं है ? अगर ऐसी बात हो तो वहां की पढ़ाई के स्तर मे सुधार करने के लिये क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : जी ऐसा कोई मेमोरेंडम तो मेरे पास नहीं आया है लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि अक्सर लड़के यह आशा करते हैं कि इन आयुर्वेदिक युनिवर-सिटियां या कालिज से निकल कर व डाक्टर बन जायेंगे और जब वह डाक्टर नहीं बनते हैं तो फिर निराश होते हैं ।

श्री बी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्राणी जी यह बतलाने की कृपा करेंगी कि कि यह जो कमेटी बनी है, इसका प्रयोजन क्या है, क्या सिर्फ आरगनाइजेशन के साथ इस का संबंध है, या सिलेबस के साथ संबंध है, या काम करने के तरीके से संबंध है ?

डा० सुशीला नायर : सारे के सारे कालेज के भविष्य का क्या नक्शा होना चाहिए, उस के साथ संबंध है ।

Shri P. R. Patel: May I know whether it is a fact that the Tibbia College of Unani medicine advertised the starting of a condensed course, and after that advertisement, so many students had applied, but nothing has been done and the course has not been started, and if so, why this college cannot be taken possession of and administered by the Centre?

Mr. Speaker: That is a suggestion for action.

Shrimati Savitri Nigam: May I know the terms of reference given particularly to this committee?

Dr. Sushila Nayar: I have already stated what the function of the committee is.

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्रणी जी को यह बात मालूम है कि चूंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पढ़ाइयां इन कालेजों में हो रही हैं और कोई एक पाठ्य-क्रम निश्चित नहीं है, इसलिए यह बहुत आवश्य हो गया है कि इस कालेज को हाथ में लेकर इस को पढ़ाई इस तरह से निश्चित की जाय कि सब जगह पाठ्यक्रम सुधर सके ? क्या इस बात पर विचार करके सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस कालेज को हाथ में ले लिया जाए ?

डा० सुशीला नायर : यह कहना कि इस कालेज के द्वारा सारे देश का पाठ्यक्रम सुधरेगा यह तो जरा बहुत ज्यादा बात हो जाती है, क्योंकि सभी कालेज वाले समझते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम से सारे देश का पाठ्यक्रम सुधरेगा । सब कालेजिज में एक तरह का पाठ्यक्रम हो, इस विचार से एक पाठ्यक्रम बनाया गया था ।

उसके बाद पंडित शिव शर्मा और दूसरे लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई। हाल ही में प्लानिंग कमीशन ने इस बारे में मीटिंग बुलाई थी कि भविष्य का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिये। उस पर विचार हो रहा है।

Designs of Thermal Stations in India

*728. **Dr. K. L. Rao:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) what are the amounts spent and committed on foreign consultants in respect of Thermal Power Station designs and Hydro Power Stations respectively;

(b) what steps are being taken to reduce the consultation fees for the designs made outside the country: and

(c) whether Government will strengthen their design organisations and also made use of indigenous consultants, if any, so as to make the designs of thermal stations in India itself?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Payments to foreign Consultants are made by the Project authorities concerned in accordance with the Agreements entered into between them Information about payments actually made is not available but the commitments of foreign exchange on this account are approximately as follows:

	Rs. in Crores.
Thermal.	3.22
Hydro.	1.46

(b) and (c). An organisation is in the process of being set up in the Power Wing of the Central Water and Power Commission to provide specialised services covering engineering, designs, procurement and installation of large Thermal and Hydro Power Stations in the country. Under this scheme, our own engineers are being given specialized training in India as well as abroad so that the latest techniques and practices employed by the more advanced countries in this particular field could be utilized by them in handling similar jobs in the country without the help of foreign Consultants.

Dr. K. L. Rao: May I know whether there is any proposal to organise a special training class for the staff engaged in designs of thermal plants with the assistance of foreign experts, if necessary?

Shri Alagesan: In the statement itself it is said that our own engineers...

Mr. Speaker: Whatever is said in the statement need not be repeated. If it is contained in the statement, then the answer need not be given.

Shri Alagesan: If any other effort is required in this direction, we are prepared to consider.

Dr. K. L. Rao: May I know whether a special investigation unit will be attached to these design offices as an adjunct for obtaining the information on water planning, coal mining and coal supply which generally cause a lot of delay in the preparation of the designs.

Shri Alagesan: Yes, we have already created a cell in the CWPC to look after these things and plan these things.

Shri Sham Lal Saraf: May I know whether Government have by now gained the experience that our scientists and other experts in the country will be better suited for taking up these designs and planning of these projects?

Shri Alagesan: As far as hydro-electric projects go, I may tell the House that we are not dependent on foreign consultants. The work of specifications, designs, planning etc. is being looked after by our people, except in the case of those projects where we receive foreign aid and where such consultancy is insisted upon by the aid-giving country. Only with regard to the thermal sector, we